Millennium Development Goals of poverty eradication, achieving universal primary education and improving maternal health, had been published in the publication "Millennium Development Goals-Final Country Report of India, 2017" which is on the website of the Ministry. The information regarding present rank or status of India globally in achieving Millennium Development Goals (MDGs) is not maintained by the Ministry. The United Nations have a website for monitoring the MDGs progress status by country and regional grouping. The Millennium Development Goals of the United Nations were eight international development goals that were to be achieved by 2015. The United Nations have since adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) to be achieved by member countries by 2030. The SDGs comprise 17 goals, 169 targets and around 232 global indicators. Government has prepared the National Indicator Framework for monitoring SDGs in consultation with Central Ministries and Departments. NITI Aayog is responsible for implementation of SDGs and mapping of the Central Sector Schemes to the SDGs. They have recently released an SDG India Index Baseline Report 2018 and a Dashboard on the Index.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS†

Bringing suitable legislation for welfare of widows in the country

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I want to make a humble request. Some of the Members, who had given their names to participate in the debate on this Resolution, could not speak because of the din in the House the other day. They want to speak on this Resolution. They are all very learned Members. I think, their inputs can be very much helpful for this Resolution.

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, श्री तिरुची शिवा का यह प्राइवेट रिजॉल्यूशन बहुत ही संवेदनशील और मानवीय मुद्दे से जुड़ा है। हम लोग इस विषय को दिनांक 10-08-2018 को, यानी इससे पहले भी एक बार डिसकस कर चुके हैं और पुनः दिनांक 21-12-2018 पर हम लोगों ने इस पर चर्चा की और जितना निर्धारित समय था, उससे अधिक ले चुके हैं। जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके तहत अब हम इस बहस को आगे चलाएंगे और माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपना जवाब दे रहे थे, उसे वे पूरा करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्माः उपसभापति महोदय, यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**...

† Further discussion continued from 10th August 2018, and 21st December, 2018.

श्री उपसभापतिः आप बोल चुके हैं। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब पूरा करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्माः माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा समय और दे दें। पिछली बार जब इस पर बहस चल रही थी, तब हाउस डिस्टर्ब्ड था, बहुत शोर था। उस समय बात नहीं हो पाई थी। ...**(व्यवधान)**... श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, कृपया आप अपनी बात बोलें। आप कंटीन्यू करें। ...**(व्यवधान)**...

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वीरेन्द्र कुमार): माननीय उपसभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आप बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी, कृपया आप बोलें और अपनी बात कंटीन्यू करें। ...**(व्यवधान)**...

डा. वीरेन्द्र कुमारः सभापति जी, उस दिन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रारम्भ की थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः सिर्फ मंत्री जी की बात के अलावा और किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखें। ...**(व्यवधान)**...

डा. वीरेन्द्र कुमारः महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए पूरे देश में विधवाओं के कल्याण के लिए काफी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उसमें सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला स्तर पर एक विधवा सेल बनाने, जिला एवं राज्य स्तर पर उनके निरीक्षणों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधवा सेल में विधवाओं के पंजीकरण, डॉक्युमेंट्स के डॉक्युमेंटेशन, शिकायत निवारण हेल्पलाइन और हेल्प डैस्क, आश्रय स्थल, स्वास्थ्य सेवाएं एवं कानूनी मदद, काउंसिलिंग, जीवन निर्वाह, गृह योजनाओं, बच्चों तथा विधवाओं की संपत्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी और अन्य जिलों के जो विधवा सेल हैं, उनसे भी तालमेल कर के, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विधवा कल्याण के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ...**(व्यवधान)**... विधवाओं सहित सुधार गृह के सभी लाभार्थियों को ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, एक मिनट रुकिए।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order under Rule 239. It says, "When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any Member has occasion to ask a question of another Member on any matter then under the consideration of the Council, he shall ask the question through the Chairman."

Sir, can I be allowed to proceed?

श्री उपसभापतिः अभी नहीं।

दरअसल, माननीय सदस्य का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर हम लोग दो बार चर्चा कर चुके हैं। मैंने इस बारे में आपको बताया और स्पष्ट किया कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें। Point of order is not allowed

डा. वीरेन्द्र कुमारः माननीय उपसभापति जी, मंत्रालय ने विधवाओं सहित सुधार गृह के सभी लाभार्थियों का डेटा बेस्ड एमआईएस विकसित किया है। इसमें लाभार्थी विधवाओं के स्वास्थ्य कारण, वित्तीय और अन्य बातों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल फाइल भी तैयार की गई है। भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है कि विधवाओं का नाम, उनके पति के मृत्यु प्रमाणपत्र पर अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी जारी कर दिया गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। ...**(व्यवधान)**...

डा. वीरेन्द्र कुमारः उपसभापति महोदय, पहले अन्य संस्थाओं द्वारा विधवाओं के लिए जो पैसा एकत्रित किया जाता था, वह अब विधवा सेल के जरिए एकत्रित किया जाएगा। इस तरह से उस राशि का उपयोग विधवाओं के कल्याण के लिए होगा। मंत्रालय महिला पुलिस स्वयं सेवी योजनाओं के जरिए विधवाओं पर हिंसा, बेदखली, धमकी की रिपोर्ट ...**(व्यवधान)**... पुलिस को देती है। इसके अलावा उनमें जागरुकता उत्पन्न करने के लिए भी उस तरह के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।

महोदय, महिला हेल्पलाइन 181 के साथ ही साथ जो हिंसा पीड़ित महिला होती है, ऐसी सभी हिंसा उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए वन स्टाफ सेंटर के माध्यम से भी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रारंभ किया गया है।

महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना के माध्यम से विधवाओं को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई है।

इसके साथ ही साथ नालसा और डालसा के माध्यम से जो सुधार गृह हैं, वे राज्य सरकार के हैं, इनके सभी लाभार्थियों को कानूनी मदद देने की पहल हुई। नालसा के माध्यम से जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके माध्यम से सुधार गृह और आश्रय गृह की विधवा महिलाओं को कानूनी मदद देने की पहल की गई है। इसके साथ ही साथ डालसा ने विधवाओं के लिए एक समर्पित कानूनी सलाह, वकील इत्यादि की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही साथ उनके पुनर्वास के लिए, उनके परिवारों से उन्हें दुबारा मिलाने के लिए भी पहल प्रारंभ की गई है।

महोदय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता विकास मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि वे विधवाओं के कौशल विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[डा. वीरेन्द्र कुमार]

महोदय, आवास और शहरी मंत्रालय के ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह अनुरोध किया गया है कि विभिन्न एजेंसियों से तालमेल करके, उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार और बाजार में समन्वय स्थापित करने की व्यवसथा की जाए। राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही साथ **...(व्यवधान)...**

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति जी **...(व्यवधान)...**

डा. वीरेन्द्र कुमारः हमारे उद्यमिता मंत्रालय और प्रशिक्षण विकास मंत्रालय **...(व्यवधान)...** कौशल विकास के जो **...(व्यवधान)...** प्रशिक्षण हैं **...(व्यवधान)...** उन कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से हमारे ऐसी सारी विधवा बहनों के लिए **...(व्यवधान)...** प्रशिक्षण देने के बाद राष्ट्रीय महिला कोष **...(व्यवधान)...** और बैंकों के माध्यम से वित्तीय ऋण उपलब्ध कराकर उनको अपना स्वयं का काम प्रारंभ करने के लिए **...(व्यवधान)...** मदद की जाए। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती जया बच्चनः उपसभापति जी **...(व्यवधान)...**

डा. वीरेन्द्र कुमारः ये सारे के सारे प्रयास मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। सर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का इसमें समावेश हो गया है। **...(व्यवधान)...** मंत्रालय ने एक प्रयोग के तौर पर मथुरा, वृंदावन में एक विधवा आश्रम की पहल की है। यह काफी अच्छा विधवा गृह बनाया गया है। इसमें पंच सितारा होटल के जैसी सारी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यह विधवा गृह तीन मंजिला है, जिसमें रैंप भी बनाया गया है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है, जिसमें चिकित्सा की व्यवस्थाएं, कानूनी मदद आदि की सारी व्यवस्थाएं वहां रखी गई हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग पूरी तरह से और अच्छा होने के बाद, बाकी राज्यों में भी, जहां पर संभावना होगी, बाकी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आने पर, वहां पर भी इस तरह के विधवा गृह प्रारंभ करने की पहल की जाएगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल के माध्यम से जिस तरह की अपेक्षाएं कीं है, उन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार इस दिशा में काफी प्रभावी कदम उठा रही है, अतः मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस संकल्प को वापिस लेने की पहल करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, now you can put your points.

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have raised a very important social issue. Members from almost all the political parties have supported it because it is not regarding one political party or one section of the society. Sir, some Members who are very learned and experienced, they wanted to share their views on this debate. The other day, when the debate was about to take place, there was a very big din and pandemonium in the House. You adjourned the House later. But, Sir, in the meantime, since they could not speak in that din, you called the next speaker, and lastly the House was adjourned. So, the other Members, like Jaya Bachchanji, K.T.S. Tulsiji, Jairam Rameshji, many other Members, who are very much experienced could have added much more to the debate to the help of the Government only.

But their views have not been heard. We are very sorry for that. Of course, we are very much aware of the time constraint. But, at the same time, this House is meant for debate. We have come here to express our views on behalf of the people. It is a matter of giving only two or three minutes, and, I think, it will not cost much when we have been wasting too many number of days for no reason. So, I would humbly say that it would have been a matter of half-an-hour or fifteen minutes only.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Can I say something? तिरुची शिवा जी, हम लोगों ने इसको दो बार discuss किया है। On 10th August, 2018, four hon. Members participated in the discussion, and, on 21st December, 2018, I requested all the Members to speak. Already, two of them have spoken. ...(*Interruptions*)... Please continue with your speech, Mr. Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it was a din and we just wanted to express our sentiments and feelings. That is all. We wanted to listen to them, and, of course, their contribution would have expressed the real situation of the widows in the country.

Sir, the Minister's reply was not convincing. He has said that an ashram is there in Vrindavan. I think, many of the Members, who are from Uttar Pradesh, are very well aware, how many widows are there in Vrindavan.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, the situation is pathetic in Vrindavan.

SHRI TIRUCHI SIVA: It must be around a lakh. So many widows are stranded there. They do not have livelihood. The Government is paying only 200 rupees per month. It is only six rupees per day. How can a person live on six rupees per day?

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): The State Government of Tamil Nadu is giving... ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: It is persuading some State Governments. One or two State Governments are coming up like the State Government of Tamil Nadu but it is not so in all the States. So, what is that the Central Government has to do, and, this is what we intend to discuss here. So, Sir, after having heard the Minister's reply, I would like to place on record my views.

According to Census 2011 data, India has over five crore widows. This is the largest population of widows in any country in the world. Our Government policy has largely ignored the specific concerns faced by widows. Such exclusion given the numbers can prove costly for a significant section of our society. When a woman is married, she leaves her own family to start a new life with the family of her husband. After her husband's death, the widow is treated as an outcast. Basic human rights are taken away from her. She is stripped off any inheritance from her husband's family. Husband's family members often ill-treat or even abandon her. Disowned by

[Shri Tiruchi Siva]

her natal home, many widows are forced to beg to make ends meet. A widow is made to give up her identity and live the rest of her life in shame.

Sir, as I said, widows from 18 years of age up to the age of 70 or 75 years are there on the streets in Vrindavan. From West Bengal, from Uttar Pradesh and from many parts of the country, they just bring the widows, leave them there and go back. Imagine a girl begging in the streets? How she will be looked at?

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): It is a human crisis, Sir.

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, it is a human crisis. We are living in a civilized society and we call ourselves a democratic country, a republic country but we do not have laws in place. No legislation is there for this weaker section. No legislation, no law for these people who are disowned by their own families. What for is the Government? This is the question which compelled me to bring in this Resolution. Sir, widows are rarely able to break away from the strongly embedded cultural norms they face. Many communities even tonsure their heads once they lose their husband. They may be young or old, how sad it is. Even after losing his spouse, a man is enjoying everything in the society whereas the woman is being disgraced and ill-treated. All sort of shame is thrust on her shoulders. So, Sir, something has to be done. We are doing this and that. We call ourselves a developed country. We are sending satellites to space but we are leaving the humans in our country on the streets. What is it? Sir, before sending satellites and feeling proud of the same, we have to take care of the humans who are living in our country. That should be our main objective.

Under such circumstances, the mental as well as physical health of the widows takes a toll. The Minister of Rural Development introduced the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme. As I said earlier, it is only 200 rupees per month and it is given to the widows in the age group of 40 to 64 years. It also specifies some income norms. It says that they are eligible only if the income is less than 32 rupees on the rural side, and, less than 47 rupees on the urban side. If they earn 35 rupees per day, they are not eligible for this pension in the rural side. So, I insist that this pension scheme must be universal. There should be no norms like income, rural, urban or anything like that. A widow is a widow. You cannot brand them as to which caste they belong to or which economic criterion applies to them. A widow is being outcast not only by the family but also by the society. The Government should not have slabs or norms. It must be made universal.

Besides the lack of pension, widows also face hardship in receiving their entitlements, because they are unable to prove that their husband has died. Mentioning

the name of widow in the death certificate of the man should be made compulsory to help her access her entitlements. Moreover, couples should be encouraged to include the name of the wife into the title of her husband's land and property. This will safeguard and protect the widow after the death of her husband.

It is reassuring to see that a new shelter home has been set up for widows in Vrindavan which has facilities for only 1,000 widows. As statistics say, there are about more than one lakh. Everyone knows that. Those from Uttar Pradesh and even Jaya Bachchanji and many others who are acquainted with that know this. They have made shelter home for only 1,000 widows. However, merely setting up these shelter homes is not enough. It is important to ensure that a regulatory mechanism is set up to periodically monitor the functioning of such homes. The Government should be held accountable for the mechanism to identify beneficiaries, provide residential care to them and deploy staff as per norms with prescribed qualification and experience. Assistance should be extended to ensure proper psychological counseling, other health care amenities and legal aid services.

Merely providing social security net to widows is not sufficient. The approach of the Government should be geared towards enabling them to build their lives. If you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. Skill development programmes would help build financial independence and productivity. This would eliminate the vicious cycle of vulnerability, deprivation and poverty. Vocational training programmes may be initiated in various areas, including tailoring, garment making and packaging. Such skill development initiatives need to be scaled up by the Government to every nook and corner of the country. Ensuring access to credit and promoting Self-Help Groups would also encourage widows to create spaces to organize and develop their own strategies for change. Further, widows should also be allowed to sit for competitive examinations for jobs in Government and PSUs for which the age limit restrictions should be relaxed.

Widows in India do not enjoy any sense of care, belongingness and understanding. Grappling with loneliness, neglect and shame, we must care for them and extend our assistance. The approach of the Government to address the challenges faced by the widows needs to be more holistic which we are lacking now. It is important to not merely feed them, but to ensure that they are able to stand on their own feet. The Government must shift the welfare approach to widows to that of empowerment, to reform and enable the widows to live a more dignified and fulfilled life.

Sir, when I introduced this Resolution, at the outset itself, I mentioned that I belong to that Dravidian Movement founded by our late Periyar. He was the first man to raise voice for the widows. When he initiated the self-respect marriage movement, the marriage he presided over was the marriage of a widow. Later when

[Shri Tiruchi Siva]

Arignar Anna, the founder leader of DMK Party, and our Leader Dr. Kalaignar came to power, they enacted so many laws for the welfare of widows.

In Tamil Nadu, we can say with pride that widows are enjoying all facilities or privileges because of the Government. Some other Governments also have some legislations in place or some welfare schemes. But what is the Central Government doing as a part of the whole of the country? When you are taking away the rights of the States on many other issues, on such social issues, the Government should take up many things. The Minister has not given an assurance even. He has elaborated saying that the Government has done this and that, but we are not contented. We want the widows to live a dignified life in the society and for that we need a legislation in place. For the welfare of widows, a law has to be in place.

Sir, I insist that the Resolution must be adopted.

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री महोदय, यह पूरे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। इसके संबंध में पूरे सदन की फीलिंग्स भी आपने देखीं और चूंकि तिरुची शिवा जी ने बहुत विस्तार से बताया है, इसलिए आपका काम उनको यह बताना कि आपकी स्कीम्स क्या हैं। मैं यह रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए कहना चाहूंगा कि अगर समय होता और परम्परा एवं कानून होते, तो मैं और लोगों को भी बोलने का आग्रह करता, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तिरुची शिवा जी ने जो कहा, यदि आप अपने जवाब के माध्यम से कुछ और कहना चाहें, तो यह आप और वे तय करें, नहीं तो मैं प्रोसेस में आगे जाऊंगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वीरेन्द्र कुमार)ः महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो बात रखी गयी है, मैंने अपने उद्बोधन में उनमें से बहुत सारे बिन्दुओं को उल्लेखित किया है। सरकार के द्वारा किये जा रहे कामों के बारे में बताया है। सरकार विधवाओं के कल्याण के लिए जो-जो स्कीम्स लेकर आ रही है, चाहे उनके कौशल विकास की बात हो, उनकी कानूनी मदद की बात हो, उनकी चिकित्सा सुविधाओं की बात हो या उनके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम जोड़े जाने की बात हो, ताकि उनके बीमा क्लेम, पॉलिसी, बैंक तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी उनको मदद मिल सके। सरकार हर तरीके से विधवाओं के कल्याण के लिए प्रयासरत है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, it is not holistic. ...(*Interruptions*)... Whatever they are doing is not holistic. They are still lacking. As I said, even the pension scheme has slabs and many other things are there. It is not sufficient. That is why we need a legislation. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tiruchi Siva, are you withdrawing the Resolution or should I put it to vote?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am not withdrawing. Please put it to vote.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Tiruchiji, the House agrees with your suggestions — the Government also. So, I want to request you to please withdraw it. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): You should pass it unanimously. ...(*Interruptions*)... Mr. Deputy Chairman, through you, I request the Government to pass it unanimously. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Does he have the leave of the House to withdraw the Resolution? ...(*Interruptions*)... The Resolution is withdrawn. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: No, Sir. ...(*Interruptions*)... Sir, this is not a political issue. ...(*Interruptions*)... If they vote against it, the Government will be exposed. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Resolution to vote. ...(*Interruptions*)... Let the lobbies be cleared. ...(*Interruptions*)... The process has started to clear the lobbies. ...(*Interruptions*)... Please keep quiet. ...(*Interruptions*)... प्लीज़ आप सब बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** Let the lobbies be cleared. ...(*Interruptions*)... आप सब बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** डिवीज़न बेल बज रही है। **...(व्यवधान)...** Let the lobbies be cleared. ...(*Interruptions*)... लॉबीज़ क्लियर हो रही हैं। **...(व्यवधान)...** आप सब कृपया अपनी जगह पर बैठें। **...(व्यवधान)...** लॉबीज़ क्लियर हो रही हैं। **...(व्यवधान)...** अपनी जगह पर बैठें। **...(व्यवधान)...** भूपेन्द्र जी, मैं आग्रह करूँगा कि आप अपनी जगह पर बैठें। **...(व्यवधान)...** भूपेन्द्र जी, आप अपनी जगह पर बैठें। **...(व्यवधान)...** आप कृपया अपनी-अपनी जगहों पर बैठें। **...(व्यवधान)...** आप प्लीज़ अपनी जगह पर बैठें। **...(व्यवधान)...**

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, the Members who are not here are being allowed. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, this is not...(*Interruptions*)...

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः नो पॉइंट ऑफ आर्डर। आप कृपया अपनी-अपनी जगह बैठिए। **...(व्यवधान)...** No, no. ...(*Interruptions*)... कृपया आपस में बात न करें। **...(व्यवधान)...** No point of order. चेयर के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। **...(व्यवधान)...** साढ़े तीन मिनट तक bell बजती है ताकि माननीय सदस्य सदन में आ सकें। **...(व्यवधान)...** आप कृपया बैठिए। **...(व्यवधान)...** The Secretary-General will now explain the voting procedure. ...(*Interruptions*)...

SHRI VIJAY GOEL: Sir, let the lobbies be cleared. ...(*Interruptions*)...

3.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Lobbies are cleared. ...(*Interruptions*)... Please sit down. The Secretary-General will now explain the voting procedure. ...(*Interruptions*)... आप कृपया अपनी-अपनी जगह बैठिए। **...(व्यवधान)...** राकेश जी, कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। **...(व्यवधान)...** कृपया अपनी-अपनी जगहों पर जाकर बैठिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:–

"Having regard to the fact that:–

(i) according to the Census of 2011, the population of widows in India is 4,32,61,278 which accounts for 7.37 per cent of the female population in India, which is the largest population of widows in the entire world;

(ii) widowhood in India is not an ideal social condition and remarriage of widows is a rare phenomenon as widows in India face problems on economic, social, legal and health fronts;

(iii) most of the widowed women do not have any formal training or education and as a result they are not able to find any employment to earn their livelihood and the conditions are worse for those widows who belong to the unorganised sector, which constitutes 70 per cent of India's population;

(iv) customs in the Indian society are still engrained in age old practices where death of the husband is a social phenomenon in the society which affects every aspect of the life of the widow and many of them suffer a social death;

(v) the old structures of joint family are being transformed into new structures of nuclear family which are not able to support the widows as around 72 per cent of the female population above the age of 60 years is dependent population;

(vi) around 60 per cent of the population of widows is in the age group of 70-74 years, who require appropriate health care facilities, but contrary to that healthcare of widows is considered as a taboo and they do not have access to basic healthcare;

(vii) widows are given property rights under the Hindu Succession Act, 1956, but most widows are unaware of these rights and they suffer from the conflicts for the inheritance of property;

(viii) a study conducted by the National Commission for Women in 2016 on the condition of widows in Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal stated that 84 per cent of women who live in Swadhar Greh homes had no access to any family property and 15 per cent had no access because their children or other family members had taken away the property;

(ix) religious places like Vrindavan, Mathura, Varanasi, etc., have become home for a large number of destitute widows from all around the country who have been left by their kiths and kins and are solely dependent on the state for their food and shelter and do not have any means of livelihood;

(x) currently the Central Government does not have any specific scheme for the welfare of widows except for the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme whereas Swadhar Greh Scheme and Short Stay Home Scheme are not specifically meant for widows and cater to all categories of destitute women; and

(xi) there is no specific law or scheme addressing needs of the widows in the country, despite the fact that it has the largest population of widows in the entire world which must be recognised as a special category of destitute women, as they suffer from mental trauma and social pressures, this House urges upon the Government to:–

(a) bring a suitable legislation for the welfare of the widows in the country, which is able to address their social security needs;

(b) extend adequate financial assistance at par with current living standards to the destitute widows;

(c) frame a policy that enables widows to get appropriate legal aid and health care;

(d) initiate awareness programmes to make people more sensitive to the social pressures faced by widows in the country; and

(e) conduct a relevant study regarding the condition of the widows in the country and use the study report to take necessary steps for their welfare."

The House Divided.

श्री उपसभापतिः कृपया शांति बनाए रखें।...**(व्यवधान)**... कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... यह कोई तरीका नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मिस्टर नीरज शेखर, कृपया आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... राकेश जी, कृपया आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... Mr. Tiruchi Siva. ...(*Interruptions*)... Shri Tiruchi Siva. ...(*Interruptions*)... राकेश जी, प्लीज बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 25

Noes: 38

Ayes — 25

Bachchan, Shrimati Jaya

Bhattacharya, Shri P.

Chandrashekhar, Shri G. C.

Hariprasad, Shri B. K.

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kalita, Shri Bhubaneswar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Khan, Shri Mohd. Ali

Nagar, Shri Surendra Singh

Ragesh, Shri K. K.

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Selja, Kumari

Seth, Shri Sanjay

Shekhar, Shri Neeraj

Siva, Shri Tiruchi

Somaprasad, Shri K.

Tamta, Shri Pradeep

Tulsi, Shri K.T.S.

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Viswam, Shri Binoy

Yajnik, Dr. Amee

Noes — 38

Agrawal, Dr. Anil

Alphons, Shri K. J.

Bajpai, Dr. Ashok

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Hanumanthaiah, Dr. L.

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kardam, Shrimati Kanta

Mahatme, Dr. Vikas

Mansingh, Dr. Sonal

Muraleedharan, Shri V.

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Poddar, Shri Mahesh

Prasad, Shri Ravi Shankar

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Shakal, Shri Ram

Singh, Shri Ajay Pratap

Sinha, Shri R. K.

Soni, Shri Kailash

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D. P.

Verma, Shri Ramkumar

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

The motion was negatived.

श्री उपसभापतिः कृपया लॉबी ओपन करें।

इसके पहले कि मैं दूसरे Resolution पर चर्चा करूं, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि घंटी बजने के साढ़े तीन मिनट तक सदस्य अंदर आ सकते हैं।

Adoption of new methods of implementing reservation benefits

Now, Dr. Vikas Mahatme to move a Resolution urging the Government to adopt a new method of implementing reservation policies, namely the "Weighted Indexing System" and appoint a Commission to determine the criteria for assessing backwardness, create a statistical formula to determine the Weighted Indexing System score for every individual; and ensure reservation benefits for SCs, STs and OBCs in Central Government Institutions. आप अपना Resolution मूव करें। **...(व्यवधान)...** कृप्या टिप्पणी न करें। **...(व्यवधान)...** यह कोई तरीका नहीं है। **...(व्यवधान)...** कृपया आप अपनी सीट पर बैठें। **...(व्यवधान)...** कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): *

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँः—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि—

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार तथा केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सर्वाधिक पिछड़े, वंचित तथा सीमांत पर रहे समूहों के उत्थान और लाभ के लिए आरक्षण एवं सकारात्मक कार्यक्रमों के लाभों के उपयोग के बारे में नीतियां मौजूद हैं जिससे अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है।

(ii) भारत में आरक्षण से होने वाले लाभों के लंबे इतिहास के बावजूद, इस नीति को क्रियान्वित करने की वर्तमान पद्धति सर्वाधिक वंचित समूहों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में असफल रही है और इस पद्धति ने, ऐसे समूहों में, जिन्हें आरक्षण के पर्याप्त लाभ नहीं मिल सके हैं, असंतोष की भावना को पैदा किया है;

(iii) अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की जांच हेतु आयोग द्वारा तैयार किए गए परामर्श पत्र, जिसे विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है तथा जो गत पांच वर्षों के दौरान ओबीसी कोटा के अंतर्गत दी गई 1.3 लाख केन्द्रीय सरकार की नौकरियों तथा गत तीन वर्षों में केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के हुए दाखिलों पर आधारित है, के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय स्तर पर मौजूद सभी आरक्षण लाभों का लगभग 97%, केवल लगभग 25% ओबीसी समूहों द्वारा लिया गया है तथा 37% ओबीसी समूहों को कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है;

---

* Not recorded.